



55

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० गवालियर

R25-15-39-II-16

/2016 पुनरावलोकन

देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोरीशंकर
श्रीवास्तव निवासी- ग्राम भद्रेरा, कृषक
ग्राम धतूरा, तहसील पोहरी जिला
शिवपुरी, म०प्र० --आवेदक

प्रकरण क्रमांक
रुप० क्रमांक 17-5/16 दस्तावेज़

म०प्र० गवालियर
प्र०

बनाम

1. मथुरा प्रसाद बैरागी पुत्र श्री बद्रीप्रसाद
बैरागी ग्राम धतूरा, परगना पोहरी
जिला शिवपुरी, म०प्र०
2. म०प्र० शासन --अनावेदकगण

पुनरावलोकन (रिक्वी) आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म०प्र०

भू-राजस्व संहिता 1959 विलोक्षण आदेश दिनांकी
26/03/2016 पारित द्वारा श्रीमती मधुषा खरे सदस्य
राजस्व मण्डल म०प्र० गवालियर के प्रकरण क्रमांक
296-2/2013 निगरानी व उनवान देवेन्द्र कुमार बनाम
मथुराप्रसाद आदि।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन-पत्र
निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 127/1 रकवा 1.556
हैक्टर स्थित ग्राम धतूरा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी की



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1539-दो/16

जिला -शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२१.७.१६	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० के० श्रीवास्तव द्वारा यह रिव्यु प्रकरण क्रमांक १५३९-दो/१६ राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर के प्र०क० निग० २९६-दो/१३ में पारित आदेश दिनांक २६.३.१६ के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा ५१ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि का पट्टा आवेदक को म०प्र० कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी के अधिकारों को प्रदाय किया जाना विशेष उपबन्ध १९८४ के तहत दिनांक १२.१२.९६ को पट्टा पदल्ल किया गया था, जिसके आधार पर आवेदकका नाम विवादित भूमि पर बहौसियत स्वामी शासकीय राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया है। अन्त में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि रिव्यु प्रकरण स्वीकार किया जावे।</p> <p>3- आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा संहिता की धारा ५१ में पुनर्विलोकन हेतु निम्न लिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है:-</p>	

W

✓

1- किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2- मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3- कोई अन्य पर्याप्त कारण

इस पुनर्विलोकन में उपरोक्त आधारों में से कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

M

